So, Gujarat State is also being looked after.

SHRI DAULATSINHJI JADEJA: The hon. Minister's statement does not satisfy us because the reasons that he has given may apply to many other States also which have been included. May I know the reason why in Phase-II, where the oil-seeds have also been considered, Gujarat has not been included? Could it be that when Phase-II was being finalised, the State Government at that time did not put up a right case before the Central Government?

SHRI BIRENDRA SINGH RAO: I would not be able to answer that question off-hand. But the fact remains that since this programme was taken up in 1977, the progress has been unsatisfactory, rather slow. We will see to it that this programme is taken up in right earnest now.

SHRI S. B. CHAVAN: In view of the answer given by the hon Minister, I would like to ask this question. In the case of Maharashtra, there has been a terrible shortage of seeds, both in cotton as well as in jowar. It is a pity that in Maharashtra even the foundation seeds of CSH-5 was not available, due to which the cultivation of jowar of the new variety has suffered very badly. Will the Minister kindly clarify the position?

SHRI BIRENDRA SINGH RAO: I admit that there has not been enough progress in producing sufficient quantity of jowar seeds in the country. We are far short of the requirements and we are taking steps to see that jowar, bajra and maize and other seeds are also developed and produced in sufficient quantity so that all demands can be met.

श्री नवल किशोर शर्मा : सीड्स के डेवेलपमेंट के प्रोग्राम में मूंगफली के बीच के उत्पादन की भी कोई योजना है ? मूंगफली का उत्पादन जब किया जाता है तब उस में एक कीड़ा लगता है ? उस कीड़े से जो इम्यून हो क्या ऐसा बीज तैयार किया जाएगा ताकि मूंगफली का उत्पादन ज्यादा तादाद में हो सके ।

SHRI BIRENDRA SINGH RAO: We have various research programmes in this connection. But the question is not directly connected with this question, as you would kindly see. If the hon. member wants to give notice for another question asking particularly as to what progress has been made in the research for finding the disease in groundnut and other crops, I will answer that.

दिल्ली में डबल रोटी की कमी

\+

*922. **श्री रामावतार शास्त्री** :

श्री के० ए० राजन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जुलाई, 1980 के 'टाइम्स ग्राफ इण्डिया' में "ब्रेड इन शार्ट सप्लाई" शीर्ष से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार ने उपभोक्ताओं को बिना कठिनाई डबलरोटी उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाये है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) to (c). Yes, Sir. Soon after the reports about shortage of bread in Delhi were received, Delhi Administration put their enforcement machinery into operation to check that manufacturers are producing the requisite number of loaves and that the retailers are not selling bread in excess of the notified prices. The authorities of the Delhi Administration also met the representatives of the manufacturers and directions were issued to them to produce

bread to the extent of the installed capacity. A proposal received from the Delhi Administration for suitable increase in prices of bread is under consideration of the Central Government.

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और यह दुख की बात है कि कभी यहां चीनी की कमी हो जाती है और इन दिनों डबल रोटी की कमी चल रही है। दिल्ली वासियों के लिये यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार की नाक के नीचे लोगों को डबल रोटी भी नहीं मिल रही है। हम तो अपने इनके नाथ एवेन्यू की बात जानते हैं, वहां की दुकानों पर डबल रोटी उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि पार्लियामैंट हाउस के भोजनालय के अन्दर भी एक दिन डबल रोटी उपलब्ध नहीं थी। यहां बहुराष्ट्रीय कंपनी ब्रिटानिया कंपनी डबल रोटी सप्लाई करती है और माडर्न बेकरी भी डबल रोटी सप्लाई करती है, दोनों के रहते हुए भी यहां यह स्थिति है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसा कोई आंकलन किया है कि दिल्ली में प्रतिदिन कितनी रोटी की आवश्यकता होती है और इसमें ब्रिटानिया कंपनी व माडर्न बेकरी अलग-अलग कितनी रोटियां बनाते हैं ? मंत्री महोदय मेहरबानी करके पहले यह बतलायें, फिर आगे पूछेंगे।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निमाण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : मालूम नहीं, शास्त्री जी के साथ क्यों छेड़ होती है, डिपो वाले क्यों करते हैं, कभी इन्हें शुगर नहीं मिलती और कभी डबल रोटी नहीं मिलती ? बाकी सबकी तो बात यह है नहीं।

श्री रामावतार शास्त्री : यह कहकर टालिये मत। यह शास्त्री जी का सवाल नहीं है, पूरी दिल्ली का सवाल है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : जहां तक इस वक्त डबल रोटी की पोजीशन है, दिल्ली में, मेरी इत्तिला के मुताबिक वह ठीक है, कोई शार्टेज नहीं है। कीमत इसकी दिल्ली में स्टैट्युटरी है, दिल्ली प्रशासन तय करता है और उसी कीमत पर डबलरोटियां दिल्ली में बिक रही हैं। कीमत भी यह है कि 200 ग्राम की डबल रोटी 55 पैसे, 400 ग्राम की 1 पया और 800 ग्राम का एक रुपये 95 पैसे पर मिल रही हैं। प्रोडक्शन भी इनकी काफी है। माडर्न बेकरी तो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा प्रोडक्शन करती है। दिल्ली से बाहर भी रोटी जाने पर पाबन्दी है। इसलिये जितनी प्रोडक्शन दिल्ली में हो रही है, 42 के करीब बेकरीज हैं जिनमें बड़ी-बड़ी तो माडर्न बेकरी, नन्दी, ब्रिटानिया, ब्लू-बर्ड हैं और इसके अलावा बहुत सी बेकरीज हैं। रोटी दिल्ली से बाहर भी नहीं जाती है, इसलिये यहां डबल रोटी का कमी नहीं होनी चाहिये।

श्री रामावतार शास्त्री : प्रोडक्शन कितनी है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : 31 लाख 75 हजार 243 लोफ तैयार किये हैं 400 ग्राम के और 800 ग्राम के 12 लाख।

अध्यक्ष महोय : प्रोडक्शन के आंकड़ों से काम चलेगा क्या ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : स्पीकर साहब इन्होंने पूछा है, अगर इनकी तसल्ली आंकड़ों से हो जाये तो मेरे ख्याल में आप बताने की इजाजत दें 1200 ग्राम के 63 लोफ़ तैयार हुए हैं। जहां तक माडर्न बेकरीज का ताल्लुक है, 400 ग्राम 4,01,279, 800 ग्राम : 10,32,232, 800 ग्राम फ्रूट वाली : 2,67,213—ये आसानी से मिल जाती हैं। इनको खरीदने वाले माननीय सदस्य जैसे शौकीन बहुत कम हैं। वह यही खाया करें।

अगर आप इजाजत दें, तो ब्लू बर्ड का उत्पादन भी बता दूं। वैसे माननीय सदस्य ने सिर्फ दो कम्पनियों के बारे में पूछा है।

श्री रामावतार शास्त्री : जहां तक मुझे इल्म है, डबल रोटी की बनावटी कमी दाम बढ़वाने के लिए की जा रही है। ब्रिटेनिया कम्पनी एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी है। उसको तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिलना चाहिए, ताकि वह उसको अपने यहां ले जा सके। मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि दिल्ली प्रशासन ने डबल रोटी की कीमतों में वृद्धि करने के लिए कोई प्रस्ताव उनके पास भेजा है, जिस पर वह विचार कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली प्रशासन ने कितनी वृद्धि सजेस्ट की है, ताकि दिल्ली वासियों को पहले ही पता चल जाये कि उन्हें किस स्थिति का सामना करना पड़ेगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : डबल रोटी की कीमत दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन तय करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं। यह दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का प्रस्ताव नहीं है। यह मांग डबल रोटी बनाने वालों की तरफ से है कि मैदे और फ्लोअर की कीमत बढ़ गई है, इस लिए कुछ भाव बढ़ाया जाये। हिन्दुस्तान में और जगहों की निस्बत दिल्ली में डबल रोटी की कीमत सब से कम बताई गई है। इसलिए दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रोपोजल पर विचार कर रहा है।

श्री रामावतार शास्त्री : वह प्रोपोजल क्या है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : अभी प्रोपोजल नहीं बना है। कोई कीमत तय नहीं हुई है। वे लोग मांग कर रहे हैं। क्या कीमत होगी, यह अभी पता नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैनुफैक्चरर्ज ने अपनी मांग को दिल्ली प्रशासन के सामने रखा होगा। उनकी मांग क्या है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मैंने अर्ज किया है कि उन्होंने अपना हिसाब-किताब बताया है उसके बाद दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन क्या तय करता है, यह बाद में देखा जायेगा।

श्री रामावतार शास्त्री : डबल रोटी बनाने वालों का क्या प्रस्ताव है—दस पैसे, बीस पैसे, एक रुपये की वृद्धि ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : उन्होंने जो हिसाब बताया है, वह मेरे पास है कि कितना खर्चा बढ़ गया है। उन्होंने क्या कीमत मांगी है, यह मेरे पास नहीं है।

श्री प्रताप भानु शर्मा : ब्रड मैनुफैक्चरर्ज ने बढ़े हुए दामों की बात कही है। उसके ऊपर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को फैसला करना है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसकी वजह से उत्पादन में गिरावट आई है पिछले माह में या इस माह में, यदि हां, तो उसका प्रतिशत क्या है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: उत्पादन में गिरावट नहीं आई है, बल्कि उत्पादन बढ़ा है। जून के मुकाबले में जुलाई के उत्पादन में गिरावट नहीं आई है। ब्रिटेनिया कम्पनी का प्रोडक्शन जून में 400 ग्राम का 29 लाख और जुलाई में 31 लाख था। नन्दी बेकरीज का प्रोडक्शन जून में 200 ग्राम का 23,000 और 400 ग्राम का 14,000 था, जबकि जुलाई, में 400 ग्राम का बढ़ कर 3,16,000 हो गया और 800 ग्राम का 28,000 हो गया—उत्पादन बहुत काफी बढ़ गया है। माडर्न बेकरीज का उत्पादन जून में 400 ग्राम का 4 लाख था, जबकि जुलाई में वह 7 लाख हो गया। दिल्ली में उत्पादन काफी बढ़ गया है और कमी की वजह से कोई कीमत ज्यादा नहीं हुई है।

SHRI R. L. BHATIA: I would like to know from the hon. Minister whether the present shortage of bread is due to the fact that there is a

change in the policy of the Government for supply of wheat to flour mills. Normally the flour mills were being supplied wheat fifty per cent over and above their grinding capacity, and now there is a change in the policy of the Government, and for lack of supply of wheat, the flour mills have not been able to produce as much maida as they could do earlier. That is the cause of shortage in the supply of bread. Is that not a fact?

SHRI BIRENDRA SINGH RAO: I have not said that there is any shortage of bread. On the contrary, the production of Modern Bakeries, for instance, has almost doubled since June, in July. In respect of 400 grams, as against four lakhs produced in June, it is seven lakhs in July; in 800 grams, as against 10 lakhs produced in June, it is 25 lakhs in July; it has more than doubled.

MR. SPEAKER: Next Question. Mr. Chandrasekhara Murthy.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली का डबल रोटी का मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, बहुत हो गया इस पर ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : रोटी तो मिलती नहीं है और राव साहब कहते हैं कि रोटी की कमी नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : यह रोजी रोटी का नहीं, डबल रोटी का मामला है ।

Farm Debt Relief Policy

+

*923. SHRI M. V. CHANDRASHEKHARA MURTHY:
SHRI P. M. SAYEED:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Central Government have taken final decision in regard to farm debt relief policy;

(b) if so, whether Central Government have asked the State Governments to furnish a list showing number of farmers who were given loan but have not been able to pay with interest;

(c) the number of such farmers in the States;

(d) whether these farmers include sugarcane growers also;

(e) whether many State Governments have already taken the decision in this regard; and

(f) if so, how many farmers in the country will be benefited by this decision?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a), (e) & (f). A statement is placed on the Table of the House.

(b) to (d). A survey of rural indebtedness for the agricultural year 1980-81 is proposed to be undertaken and the State Governments have been requested to assist in the survey work. Information about the number of farmers in different States and the extent of their indebtedness and other relevant details would be available only after the survey has been carried out.

Statement

1. Farm debts arise out of loans taken from institutional agencies as well as non-institutional sources such as money lenders. As a part of the 20-Point Programme, Government of India had issued guidelines in August, 1975 to the State Governments and Union Territory Administrations for undertaking legislative measures to provide relief from indebtedness. This relief related to loans from non-institutional agencies borrowed by weakers sections. Under these guidelines the State Governments and Union Territory Administartion were to impose moratorium on recovery of debts